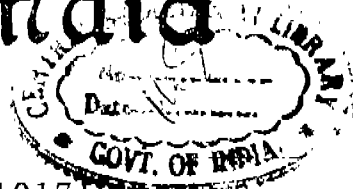




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 16, 1996 (फाल्गुन 26, 1917)  
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 16, 1996 (PHALGUNA 26, 1917)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सक) (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, प्रादेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 309	भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक प्रादेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप को उपलब्धियों भी शामिल है) के हिन्दी अधिष्ठत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ *
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	217	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और प्रादेश	*
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक प्रादेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	3	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अदीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	217
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	315	भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	285
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड 3—मुख्य व्यक्तियों के प्राधिकार के अधीन प्रत्येक द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	--
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, प्रादेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।	2971
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	51
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के प्रादेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के प्रांक्तों को बनाने वाला अनुसूचक	*
भाग I—खण्ड 3—उप खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक प्रादेश और अधिसूचनाएं	*		

## CONTENTS

	PAGE		PAGE
<b>PART I—SECTION 1</b> —Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	309	<b>PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)</b> —Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . .	*
<b>PART I—SECTION 2</b> —Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	217	<b>PART II—SECTION 4</b> —Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	*
<b>PART I—SECTION 3</b> —Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	3	<b>PART III—SECTION 1</b> —Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . . . .	217
<b>PART I—SECTION 4</b> —Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence . . . . .	315	<b>PART III—SECTION 2</b> —Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . . .	205
<b>PART II—SECTION 1</b> —Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	<b>PART III—SECTION 3</b> —Notifications issued by, or under the authority of Chief Commissioners . . . . .	—
<b>PART II—SECTION 1-A</b> —Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	<b>PART III—SECTION 4</b> —Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . .	2971
<b>PART II—SECTION 2</b> —Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . .	*	<b>PART IV</b> —Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . . . . .	51
<b>PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)</b> —General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*	<b>PART IV</b> —Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc., both in English and Hindi . . . . .	*
<b>PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)</b> —Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories). . . . .	*		

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 1995

संकल्प

सं. 19-2/95-फसल प्रशासन-5.—भारत सरकार ने इस मंत्रालय के दिनांक 14 सितम्बर, 1992 के संकल्प संख्या 24-3/89 फसल प्रशासन-2 द्वारा गठित भारतीय जूट विकास परिषद् का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। पुनर्गठित परिषद् में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. अध्यक्ष

भारत सरकार द्वारा नामित गैर सरकारी व्यक्ति।

2. उपाध्यक्ष

कृषि आयुक्त, कृषि मंत्रालय कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।

3. सदस्य

क. संसद सदस्य :

संसद के तीन सदस्य, (दो लोक सभा से तथा एक राज्य सभा से) जो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित किए जाएंगे।

ख. राज्य सरकारों के प्रतिनिधि :

निम्नलिखित राज्य सरकारों के कृषि विभाग का एक-एक प्रतिनिधि, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित किए जाएंगे।

1. आंध्र प्रदेश

2. असम

3. बिहार

4. जैवालम

5. छड़ीसा

6. त्रिपूरा

7. उत्तर प्रदेश

8. पश्चिम बंगाल

ग. केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि :

(क) सलाहकार (कृषि), योजना आयोग, नई दिल्ली।

(ख) संयुक्त सचिव (विस्तार), कृषि और सहकारिता विभाग।

(ग) जूट आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, कलकत्ता।

(घ) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली अथवा उसका नामिती।

(ङ) निदेशक, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान (भा. कृ. अ.)

(प.) बोरकपुर (पश्चिम बंगाल)।

(च) निदेशक, जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, कलकत्ता।

(छ) प्रबंध निदेशक, भारतीय जूट निगम, कलकत्ता।

(ज) कृषि और सहकारिता विभाग में जूट से संबंधित कार्य देखने वाला संयुक्त आयुक्त।

(झ) नागरिक पूर्ति मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।

घ. उत्पादकों के प्रतिनिधि :

निम्नलिखित जूट/मस्ता उत्पादक राज्यों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित किए जाने वाले उत्पादकों का एक प्रतिनिधि :—

(प्रतिनिधियों की संख्या)

1. आंध्र प्रदेश

एक

2. असम

एक

3. बिहार

एक

4. जैवालम

एक

5. छड़ीसा

एक

6. त्रिपूरा

एक

7. उत्तर प्रदेश

एक

8. पश्चिम बंगाल

एक

ड. व्यापार प्रतिनिधि :

जूट ओटार्ड कर्ता संघ का एक प्रतिनिधि ।

च. उद्योग प्रतिनिधि :

भारतीय जूट मिल संघ, कलकत्ता का एक प्रतिनिधि ।

छ. मजदूरों के प्रतिनिधि :

1. फार्मी में कार्यरत मजदूर एक
2. कारखानों के कार्यरत मजदूर एक

ज. ऐसे अन्य व्यक्ति, जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामित किए जाएं ।

4. सदस्य सचिव :

निदेशक, जूट विकास निदेशालय, 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, निजाम पैलेस परिसर, कलकत्ता-700020 ।

5. प्रक्षक : (जो परिषद् के सदस्य नहीं होंगे, बल्कि परिषद् के विचार विमर्श में सहायता करने के लिए आमंत्रित किए जाएंगे) ।

1. अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम अथवा उनका नामित/प्रतिनिधि ।
2. कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय अथवा उनका प्रतिनिधि ।
3. वित्तीय सलाहकार, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ।
4. अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि ।
5. पौध संरक्षण सलाहकार, भारत सरकार, कृषि और सहकारिता विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि ।
6. अध्यक्ष, कृषि लागत और मूल्य आयोग अथवा उनका नामित/प्रतिनिधि ।
7. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम, नई दिल्ली ।
8. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली ।
9. राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि ।

2. परिषद् एक सलाहकार निकाय होगी और इसके निम्न-लिखित कार्य होंगे :—

1. जूट, मेस्ता और अन्य रेशेदार फसलों (कपास के अलावा) के संबंध में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों पर विचार करना, समय-समय पर

उनकी प्रगति की समीक्षा करना और जूट तथा मेस्ता के उत्पादन को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करना ।

2. जूट के उत्पादन तथा विपणन एवं जूट उत्पादकों की लाभकारी मूल्य दिलाने में संबंधित समस्याओं पर विचार करना और इन मामलों के संबंध में सरकार को सलाह देना ।
3. घरेलू तथा निर्यात मंडियों में जूट की विभिन्न किस्मों की मांग पर विचार करना तथा उत्पादन कार्यक्रमों में तदनुसार आवश्यक व्यवस्था करने के संबंध में सरकार को सलाह देना ।
4. जूट और मेस्ता के उत्पादन के संबंध में छांटने तथा सीमांत किसानों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना और उन्हें पूरा करने के लिए उचित उपाय करने हेतु सलाह देना ।
5. जूट और मेस्ता से संबंधित अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम को बीच समन्वय करना और जूट और मेस्ता की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार लाने की आवश्यकताओं के बारे में सलाह देना, और
6. आवश्यक समझे जाने वाले अन्य संबंधित मामलों पर समय-समय पर सरकार को सलाह देना ।

3. परिषद् को विशेष मामलों पर विचार करने के लिए स्थायी समिति, तकनीकी समिति और तदर्थ समिति स्थापित करने तथा विशेष प्रयोजनों के लिए आवश्यकतानुसार कृषि विश्व-विद्यालयों तथा अन्य विशेष हितों के प्रतिनिधियों जैसे सदस्यों को सहयोजित करने का अधिकार होगा ।

4. परिषद् की बैठक समय-समय पर जूट उत्पादक क्षेत्रों तथा व्यापार एवं उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होगी और भारत सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

5. परिषद् तब तक काम करती रहेगी जब तक कि सरकार के संकल्प द्वारा इसे समाप्त न कर दिया जाए । परिषद् के अध्यक्ष तथा अन्य गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल परिषद् में उनकी नामित होने की तिथि से तीन वर्षों होगा, बशर्ते भारत सरकार के विशेष आदेश द्वारा इसे अवधि को घटाया या बढ़ाया न जाए ।

6. संसद के सदस्यों में से नामित किए गए परिषद् के सदस्य संसद न रहने पर परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे ।

7. सरकारी निकायों जैसे समितियों, परिषदों आदि में काम कर रहे संसद सदस्य ऐसी निकायों की बैठकों में भाग लेने पर समय-समय पर संबंधित संसद सदस्यों के बतन भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत यात्रा/दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे ।

## आदेश

आवेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिसंघल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आवेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

वीणा उपाध्याय  
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPTT. OF AGRICULTURE & COOPN.)

New Delhi, the 15th February 1996

## RESOLUTION

No. 19-2/95-CA.V.—The Government of India has decided to reconstitute the Indian Jute Development Council, constituted *vide* this Ministry's Resolution No. 24-3/89-CA.II, dated the 14th September, 1992. The reconstituted Council will be composed as follows :—

## I. CHAIRMAN

A Non-official to be nominated by the Government of India.

## II. VICE CHAIRMAN

Agriculture Commissioner, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, New Delhi.

## III. MEMBERS

## A. MEMBERS OF PARLIAMENT

Three Members of Parliament (two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha) to be nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs.

## B. REPRESENTATIVES OF STATE GOVERNMENTS

One representative from each of the following States in the Deptt. of Agriculture to be nominated by the respective State Governments :—

- (i) Andhra Pradesh
- (ii) Assam
- (iii) Bihar
- (iv) Meghalaya
- (v) Orissa
- (vi) Tripura
- (vii) Uttar Pradesh
- (viii) West Bengal.

## C. REPRESENTATIVES OF CENTRAL GOVERNMENT

- (a) Adviser (Agriculture) Planning Commission, New Delhi.
- (b) Joint Secretary (Extension), Deptt. of Agriculture & Coopn. or his nominee.
- (c) Jute Commissioner, Ministry of Textiles, Calcutta.
- (d) Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi or his nominee.
- (e) Director, Jute Agricultural Research Institute (ICAR), Barrackpore (W. Bengal).

(f) Director, Jute Technological Research Laboratory, Calcutta.

(g) Managing Director, Jute Corporation of India, Calcutta.

(n) Joint Commissioner dealing with the jute in the Department of Agriculture & Cooperation.

(i) A representative of the Ministry of Civil Supplies.

## D. REPRESENTATIVES OF GROWERS

One Growers' representative to be nominated by the respective State Govt. from the major Jute/Mesta growing State as follows :—

(No. of representatives)

1. Andhra Pradesh	One
2. Assam	One
3. Bihar	One
4. Meghalaya	One
5. Orissa	One
6. Tripura	One
7. Uttar Pradesh	One
8. West Bengal	One

## E. REPRESENTATIVE OF TRADE

One representative of the Jute Balers' Association.

## F. REPRESENTATIVE OF INDUSTRY

One representative of the Indian Jute Mills Association, Calcutta.

## G. REPRESENTATIVES OF WORKERS

- (i) Workers engaged in Farms One
- (ii) Workers engaged in Factory One

## H. SUCH ADDITIONAL PERSONS AS MAY FROM TIME TO TIME BE NOMINATED BY THE GOVERNMENT OF INDIA.

## IV. MEMBER SECRETARY

The Director,  
Directorate of Jute Development,  
234/4 A.J. Bose Road,  
Nizam Palace Campus,  
Calcutta-700 020.

## V. OBSERVERS

(who would not be Members of the Council, but would invariably be invited to assist the Council in its deliberations).

1. Chairman State Trading Corp., or his nominee/representative.
2. Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Rural Development or his representative.

3. Financial Adviser, Department of Agriculture & Cooperation.
4. Economic and Statistical Adviser, Ministry of Agriculture, Deptt. of Agri. & Cooperation or his nominee.
5. Plant Protection Adviser to the Govt. of India, Deptt. of Agriculture & Cooperation or his nominee.
6. Chairman, Agricultural Costs and Prices Commission or his nominee/representative.
7. Managing Director, National Seeds Corporation, New Delhi.
8. Managing Director, National Cooperative Development Corporation, New Delhi.
9. A representative of the National Agricultural Co-operative Marketing Federation Ltd., New Delhi.

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

- (i) To consider development programme in the Central and State Sector in respect of Jute, Mesta and other fibre crops (excluding Cotton) thereof from time to time, and recommend measures for increasing the production of jute and mesta;
- (ii) To consider problems relating to the production and marketing of jute and remunerative prices to jute growers and advise Government in these matters;
- (iii) To consider demands for different varieties of jute in the domestic as well as export markets and advise Govt. about necessary arrangements for meeting the said demands through suitable development programme accordingly;
- (iv) To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of jute and mesta production and suggest suitable measures for meeting the same;
- (v) To facilitate coordination between Research and Development Programmes relating to jute and mesta to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of jute and mesta; and

- (vi) To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time.

3. The Council will have the powers to set up Standing Committees, Technical Committees and Ad-hoc Committee to look into specific issues and to coopt members such as representatives of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary, for specific purposes.

4. The Council will meet periodically in areas in which jute is grown and at important centres of trade and industry and will make recommendations to the Government of India.

5. The Council will continue to function until it is abolished by Resolution of the Government. The term of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Govt. of India.

6. Those members of the Council who are nominated from among Members of the Parliament will cease to be the Members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament.

7. Members of Parliament serving on Government bodies like Committees, Councils etc. are entitled to get TA/DA for attending the meetings of those bodies in accordance with the provisions of the Salary, Allowances & Pension of Members of Parliament Act, 1954 as amended from time to time and the rules made thereunder.

#### ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

VEENA UPADHYAYA,  
Joint Secy.